आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 16.01.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :—

- प्रदेश में होम स्टे योजना का लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को मिलेगा; राज्य मंत्रिमण्डल ने नई नियमावली को दी मंजूरी।
- उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच 'स्वस्थ सीमा अभियान' के तहत एमओयू। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में मजबूत होंगी स्वास्थ्य सेवाएं।
- पौड़ी ज़िले के पैठाणी स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन आज, मंदिर को मिलेगा भव्य और दिव्य स्वरूप।
- उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के गंगाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दी।

कैबिनेट

राज्य मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले चरण में ऐसे उपनल कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासन, पर्यटन, शिक्षा, न्याय और कृषि से जुड़े कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। एक रिपोर्ट—

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे और बेड—एंड—ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली—2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत अब होम स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

बैठक में केदारनाथ धाम में खच्चरों के गोबर को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पैलेट में बदलने से संबंधित एक वर्ष की अवधि के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी गई। इसके तहत गोबर और चीड़ की पत्तियों को मिलाकर बायोमास पैलेट तैयार किए जाएंगे।

बैठक में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत में विज्ञान केंद्रों के लिए कुल 12 पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने बागवानी मिशन योजना के तहत एंटीहेल नेट योजना पर राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया। वहीं पेराई सत्र 2025–26 के लिए चीनी मिलों को शासकीय प्रत्याभूति देने तथा गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य और गन्ना विकास अंशदान की दरों को निर्धारित करने पर भी सहमति दी गई।

भेंट

उपनल कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और समान कार्य–समान वेतन को लेकर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया।

उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने वाला है और इससे उनके सम्मान तथा आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साह और विश्वास का माहौल बना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

सुदृढ स्वास्थ्य सेवाएं

सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के बीच 'स्वस्थ सीमा अभियान' के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में यह एमओयू संपन्न हुआ।

इस समझौते का उद्देश्य पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के 108 सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह अभियान पहले चरण में शुरू किया जा रहा है, जिससे दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। समझौते के तहत आईटीबीपी द्वारा योग्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एमआई रूम और टेली–मेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार सीमावर्ती गांवों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी और उनके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाएगा।

वहीं राज्य सरकार संबंधित गांवों के जनसांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराएगी और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करेगी। दवाइयों और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नियमित रूप से की जाएगी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार निभाएगी।

आकाशवाणी समाचार, देहरादून

एस.आई.टी गठन

उधमसिंह नगर ज़िले के खटीमा के किसान सुखवन्त सिंह की आत्महत्या प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए विशेष जांच दल–एसआईटी का गठन किया है। पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में यह दल गठित किया गया है। इस पांच सदस्यीय एसआईटी दल में पुलिस अधीक्षक चम्पावत अजय गणपति, क्षेत्राधिकारी टनकपुर वन्दना वर्मा, निरीक्षक दिवान सिंह बिष्ट और उपनिरीक्षक मनीष खत्री को शामिल किया गया है।

निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकरण से जुड़े निलंबित तीन उपनिरीक्षक, एक अपर उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी और सात आरक्षियों सहित कुल 12 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग स्थानांतरित किया गया है।

इसके साथ ही मृतक द्वारा जारी वीडियो और ई–मेल के माध्यम से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों के तथ्यों का विस्तृत परीक्षण कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राहु मंदिर भव्य स्वरूप

पौड़ी जिले के पैठाणी में स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर को जल्द ही भव्य और दिव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए आज भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पौराणिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पावन अवसर में सहभागी बनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।

वित्तीय स्वीकृति

उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र बड़ासू पट्टी के लिए गंगाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 1 करोड़ 74 लाख 90 हजार रुपये की लागत से किया जाएगा।

पुरोला विधायक ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से बड़ासू पट्टी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार की सुविधा समय पर मिल सकेगी। इससे गर्भवती और धात्री महिलाओं की देखभाल के साथ–साथ क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

शिष्टाचार भेंट

राज्यपाल लेफ्टनेंट जनरल गुरमित सिंह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर एवं डीन (अकादमिक) डॉ. नवीन के. नवानी और विजिटिंग प्रोफेसर डॉ. एच. सी. पोखरियाल ने लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान उन्होंने आईआईटी रुड़की में आम जनजीवन से जुड़े प्रमुख शोध कार्यों की जानकारी दी। इनमें बेहतर पोषण, सुरक्षित भोजन, किसानों की आय में वृद्धि, पशुपालन में सुधार और एंटीबायोटिक के अनावश्यक उपयोग को कम करने से जुड़े शोध शामिल हैं। प्रोफेसर नवानी ने मोटे अनाज से तैयार प्रोबायोटिक युक्त मिलेट ब्रेड, बुरांश से बने स्वदेशी पेय 'रोडोबूस्ट', स्थानीय लाखोरी मिर्च और शहद की शुद्धता से संबंधित अनुसंधानों के बारे में जानकारी दी।

राज्यपाल ने इन शोध कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे व्यावहारिक और जनोपयोगी अनुसंधान समाज, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने शहद, मिलेट्स, बद्री तुलसी और उत्तराखण्ड की पारंपरिक फसलों व स्थानीय उत्पादों पर आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर शिलान्यास की गई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी इन योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जाए और उन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उनका लोकार्पण नहीं हुआ है, उनका जल्द से जल्द लोकार्पण कराया जाए ताकि आम लोगों को इनका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उन्हें तय समय–सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग सक्रियता से काम करें।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों की 22 हजार पन्द्रह करोड़ रुपये की 91 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इनमें से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 6 का लोकार्पण हो चुका है और 12 का लोकार्पण अभी बाकी है। शेष 73 परियोजनाओं पर कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है, जिनमें से अधिकांश के मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।